

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या - 162/2014 (अपील)

GCMS No. 2014/00026

बद्रीलाल आत्मज स्व० रामसुखजी जाति माली निवासी अस्पताल के पास कस्बा चेचट, नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट



अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 24.11.2014 मि०नं० 812/2014 नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा० अधि०

उपस्थिति

1. श्री रविन्द्र कुमार नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.03.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट जिला कोटा ने ग्राम चेचट की भूमि खसरा नम्बर 347 की 24 हे० एवं ख०नं० 39 की 0.40 हे० किस्म बेहड़ में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हत्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 812/2014 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 150/- रुपये का शास्ति व एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 24.11.2014 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 26.12.2014 को पेश की गई है कि अपीलान्ट ने कमी भी ख.नं. 347 व ख.नं. 39 की भूमि वाके ग्राम चेचट पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि अपीलान्ट अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि 5 बीघा पर ही काश्त कर रहा है और विवादित भूमि ख.नं. 347 व अन्य अपीलान्ट के खाते की भूमि के उत्तरी ओर स्थित है। किन्तु संबंधित हत्का पटवारी द्वारा भूमि की बिना पैमाईश किये अपीलान्ट के विरुद्ध

जिला कलेक्टर
कोटा

अतिक्रमण की रिपोर्ट निराधार तरीके से पेश की थी, इस रिपोर्ट को साबित करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय ने न तो हल्का पटवारी के बयान लेखबद्ध किये न ही अपीलांट को जवाब व जिरहा का मौका दिया है। जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए गांव के स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध करने चाहिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होते हुए भी अपने मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया है जो गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी प्रक्रिया व कानूनी प्रावधानों एवं नेचुरल जस्टिस के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट दिनांक 24.11.2014 निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावें।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने कभी भी ख.नं. 347 वख.नं. 39 की भूमि वाके ग्राम चेचट पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि अपीलांट अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि 5 बीघा पर ही काश्त कर रहा है और विवादित भूमि ख.नं. 347 व अन्य अपीलांट के खाते की भूमि के उत्तरी ओर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी प्रक्रिया व कानूनी प्रावधानों एवं नेचुरल जस्टिस के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समय पटवारी रिपोर्ट में व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील में कहीं भी अंकित नहीं है कि अपीलांट द्वारा उक्त ख.नं. की भूमि संवत् 2070 में कौन सी फसल की थी और संवत् 2071 में कौन सी फसल स्थित है। इस प्रकार आदेश अपीलांट न्यायालय नॉन स्पीकींग होने से खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में भी अपीलांट का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट से मंगवाई गई रिपोर्ट क्रमांक/355 दिनांक 4.7.2019 मय पटवारी रिपोर्ट से होती है, उक्त रिपोर्ट में ग्राम चेचट के खसरा नं0 347 रकबा 0.24 हे0 एवं खसरा नं0 39 रकबा 0.40 हे0 पर बद्रीलाल माली निवासी चेचट का कब्जा नहीं होना बताया है, ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट दिनांक 24.11.2014 निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावें।
5. परोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।



2

जिला न्यायालय
जापुर

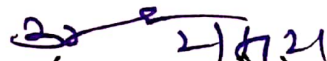
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2014 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 26.12.2014 को पेश की गई जो अन्दर मियाद है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि बद्रीलाल आत्मज स्व० रामसुखजी जाति माली निवासी अस्पताल के पास कस्बा चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने चेचट की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 347 की रकबा 0.24 हैक्टेयर एवं ख०नं० 39 रकबा 0.40 हे० में अनाधिकृत कब्जा कर फसल सोया एवं उड़द काशत किया है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत पश्चातवर्ती का नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 150/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(उज्ज्वल राठी)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा